

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली

13 फरवरी 2020

अल्पसंख्यक विकास निगम से अधिकतर मुस्लिम समुदायों को बाहर करना असम में और ज़्यादा सांप्रदायिक विभाजन का कारण बनेगा: पॉपुलर फ्रंट

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव अब्दुल वाहिद सेठ ने मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकतर हिस्से को बाहर करते हुए खिलौंजिया मुस्लिम विकास निगम का नया नाम रखने के असम अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास विभाग के फैसले पर सवाल उठाया है।

अब्दुल वाहिद सेठ ने आज मीडिया को जारी बयान में कहा कि “यह फैसला असम के धार्मिक समुदायों के बीच और ज़्यादा दरार पैदा करेगा।”

असम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रंजीत दत्ता ने यह ऐलान किया है कि खिलौंजिया और मुस्लिम शब्दों को विशेष असामी जातीय मुस्लिम समुदायों के नाम से बदलकर निगम का दूसरा नाम रखा जाएगा।

ऑल असम कोचरी समाज यह मांग करता रहा है कि असम के गैर-आदिवासी समुदायों को ‘खिलौंजिया’ या ‘स्वदेशी’ के दायरे से बाहर किया जाए। यह चीज़ बीजेपी के लिए दोधारी तलवार साबित होगी, जिससे एक तरफ जातीय आसामी मुसलमान दूसरे मुसलमानों के खिलाफ हो जाएंगे और दूसरी तरफ बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को और ज़्यादा परेशान किया जाने लगेगा।

एनआरसी लागू किए जाने और सीएबी पास होने के बाद से राज्य में पहले ही अफरा-तफरी का माहौल था और जातीय समूह भी बीजेपी के खिलाफ हो गए थे। इसलिए मौजूदा फैसले को इस तौर पर भी देखा जाना चाहिए कि यह आंदोलन कर रहे आसामी जातीय समूहों को खुश और खामोश करने की एक कोशिश है।

अब्दुल वाहिद सेठ ने सरकार से गैर-आसामी अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी कानून को वापस लेने की मांग की।

डॉक्टर मोहम्मद शमून

डायरेक्टर, जनसंपर्क

मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

नई दिल्ली